



15 March, 2024

एक राष्ट्र, एक चुनाव पर रामनाथ कोविन्द पैनल

संदर्भ: एक राष्ट्र, एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति (HLC) ने गुरुवार 14 मार्च की सुबह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंपी।

रिपोर्ट की मुख्य बातें:

- इस व्यापक रिपोर्ट में 21 खंड और 18,626 पृष्ठ शामिल हैं, जिसमें अनुलग्नकों के साथ 11 अध्याय शामिल हैं।
- इसके अतिरिक्त, सरकार ने एक राष्ट्र, एक चुनाव प्रस्ताव पर महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यू) की एक सूची जारी की है।

एक साथ चुनाव की व्याख्या:

- एक साथ चुनाव, जिसे "एक राष्ट्र, एक चुनाव" के रूप में भी जाना जाता है; में लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और शहरी तथा ग्रामीण स्थानीय निकायों सभी में एक साथ चुनाव कराना शामिल है।
- वर्तमान में, ये चुनाव स्वतंत्र रूप से आयोजित किए जाते हैं, जिससे प्रत्येक निर्वाचित निकाय की शर्तों के अनुसार अलग-अलग समय-सीमा निर्धारित होती है।

ऐतिहासिक संदर्भ:

- भारत में इससे पहले वर्ष 1957 में सात राज्यों में एक साथ चुनाव लागू किया गया था, लेकिन वर्ष 1967 में चौथे आम चुनाव के बाद यह प्रथा बंद हो गई।
- पिछले कुछ वर्षों में, चुनावों की आवृत्ति में वृद्धि हुई है, देश में हर साल पांच से छह चुनाव होते हैं, जिससे प्रशासनिक चुनौतियाँ और व्यवधान सदैव बने रहते हैं।

एक साथ चुनाव के पक्ष में तर्क:

- लोकतंत्र में उपस्थित विभिन्न कारण एक साथ चुनाव की आवश्यकता का समर्थन करते हैं, जिनमें सरकारी व्यय को कम करना, अनिश्चितता और अस्थिरता को कम करना और प्रभावी शासन सुनिश्चित करना आदि शामिल हैं।
- आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) का लगातार उपयोग और मतदाताओं की अरुचि चरणबद्ध चुनावों से जुड़ी चुनौतियों में से एक है।

पहल और अध्ययन समूह:

- एक साथ चुनाव के व्यवहार्यता की जांच करने के लिए सितंबर 2023 में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी) की स्थापना की गई थी।
- विभिन्न पृष्ठभूमियों के प्रमुख सदस्यों को शामिल करते हुए, इस समिति ने कई बैठकें कीं और इस मुद्दे का व्यापक अध्ययन करने के लिए हितधारकों के साथ काम किया।

Reviving an old debate

Centre has said a committee has been formed to explore the possibility of simultaneous polls for LS and state assemblies

PANEL FORMED

While the panel is likely going to be headed by former President Ram Nath Kovind, its composition and the terms of its functioning will be announced soon

WHAT HAS BEEN SAID ABOUT THE IDEA

NITI AAYOG

A 2016 paper, co-authored by Bibek Debroy and Kishore Desai, noted...

- Separate elections lead to massive recurring expenditures as well as prolonged deployment of forces
- It suggested holding elections in two cycles with an interregnum of 30 months
- It pegged cost of simultaneous polls at ₹4,500 crore, while the cost of 2014 Lok Sabha polls alone was ₹3,870 crore

STANDING COMMITTEE

In 2015, the House panel on personnel, public grievances, law and justice said...

- Elections could be held in two phases
- Polls to some assemblies can be held in Lok Sabha midterm and remaining assemblies could be held at the end of Lok Sabha term

LAW COMMISSION

In 1999, the Law Commission in its 170th report on Reform of Electoral Laws said...

- Holding simultaneous polls would be ideal, but a workable formula is required to be in the Constitution
- The holding of a separate election to assemblies should be an exception and not the rule
- Another law panel report, in 2018, said simultaneous polls don't alter balance of power between Union and the states

समिति की सिफारिशें:

- समिति ने दो चरणों में एक साथ चुनाव कराने के लिए संवैधानिक संशोधन का प्रस्ताव दिया है।
- यह लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के साथ नगर पालिकाओं और पंचायतों के चुनावों को सिंक्रनाइज करने का सुझाव देता है, जिसके लिए राज्यों द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता होगी।
- समिति की अन्य सिफारिशों में, एकल मतदाता सूची और चुनाव पहचान पत्र की तैयारी के साथ साथ, एक साथ चुनावों के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए, तार्किक योजना के प्रावधान शामिल हैं।

इंडो-पैसिफिक आर्थिक ढांचा

संदर्भ: केंद्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल ने हाल ही में इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरेटी (आईपीईएफ) वर्चुअल मंत्रिस्तरीय बैठक में भाग लिया है।

बैठक की चर्चाओं का अवलोकन:

- इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरेटी पर आभासी (वर्चुअल) मंत्रिस्तरीय बैठक के दौरान, आईपीईएफ भागीदारों ने नवंबर 2023 में प्रस्तावित समझौतों के लिए, वार्ता के पर्याप्त निष्कर्ष के बाद से हुई प्रगति को स्वीकार किया।
- इन भागीदारों ने तीन प्रस्तावित समझौतों पर आगे सहयोगात्मक कार्य पर चर्चा की और 24 फरवरी, 2024 को आईपीईएफ आपूर्ति श्रृंखला समझौते के लागू होने का स्वागत किया।

मंत्रिस्तरीय सभा का संबोधन:

- विभिन्न आईपीईएफ भागीदारों के कार्रवाई-उन्मुख सहयोगी तत्वों के शीघ्र कार्यान्वयन के आह्वान पर जोर दिया गया।
- इन मंत्रिस्तरीय चर्चाओं ने भारत की वैश्विक उत्पादन क्षमताओं का उल्लेख किया और स्वच्छ अर्थव्यवस्था क्षेत्र में अवसरों का पता लगाने के लिए आईपीईएफ भागीदारों के निवेशकों को आमंत्रित किया गया।

अगले कदम और पहल:

- फ्रेमवर्क के तहत ठोस परिणामों के लिए योजनाओं की रूपरेखा तैयार की गई, जिसमें नए सहकारी कार्य कार्यक्रम (सीडब्ल्यूपी) की शुरुआत और जून 2024 में सिंगापुर में आईपीईएफ स्वच्छ अर्थव्यवस्था निवेशक फोरम का उद्घाटन शामिल है।
- प्रमुख समझौतों और पहलों पर चर्चा करने के लिए मंत्रियों का 6 जून, 2024 को सिंगापुर में व्यक्तिगत रूप से मिलने का कार्यक्रम तय किया गया है।

प्रस्तावित समझौतों पर प्रगति:

- कानूनी समीक्षा पूरी होने और प्रस्तावित समझौतों को अंतिम रूप देने का प्रयास किया गया।
- प्रस्तावित समझौतों का उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण में सहयोग बढ़ाना, निष्पक्ष व्यापार और निवेश प्रथाओं को बढ़ावा देना और चल रहे आर्थिक सहयोग के लिए तंत्र स्थापित करना है।

आपूर्ति श्रृंखला लचीलेपन का निर्माण:

- आईपीईएफ आपूर्ति श्रृंखला समझौता लागू हो गया है, साझेदार समझौते को क्रियान्वित करने और सहयोग के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान करने पर काम कर रहे हैं।

Face to Face Centres





DHYEYA IAS®
most trusted since 2003

DAILY pre PARE

Current affairs summary for prelims

15 March, 2024

➤ स्वच्छ अर्थव्यवस्थाओं में तेजी से बदलाव:

- आईपीईएफ क्लीन इकोनॉमी इन्वेस्टर फोरम की योजनाएं और जलवायु बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए निजी निवेश जुटाने के लिए आईपीईएफ कैटेलेटिक कैपिटल फंड के लिए फंडिंग प्रतिबद्धताओं पर चर्चा की गई।

➤ नये सहकारी कार्य कार्यक्रम:

- चार नए सीडब्ल्यूपी की घोषणा की गई, जिसमें कार्बन बाजार, स्वच्छ बिजली वृद्धि, स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन के लिए कार्यबल विकास और टिकाऊ विमानन ईंधन जैसे क्षेत्र शामिल हैं।

➤ व्यावसायिक वातावरण में पारदर्शिता बढ़ाना:

- पारदर्शी कारोबारी माहौल को बढ़ावा देने सहित व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए प्रस्तावित निष्पक्ष अर्थव्यवस्था समझौते के तहत शुरुआती परिणामों पर चर्चा हुई।
- भ्रष्टाचार विरोधी प्रयासों और कर प्रशासन को मजबूत करने के लिए तकनीकी सहायता और क्षमता निर्माण पहल पर जोर दिया गया।

➤ आईपीईएफ के बारे में:

- मई 2022 में आरम्भ किए गए आईपीईएफ में आर्थिक सहयोग बढ़ाने का लक्ष्य रखने वाले 14 क्षेत्रीय भागीदार शामिल हैं।
- इस बातचीत से नवंबर 2023 में प्रस्तावित समझौतों का महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकला, जिसमें आपूर्ति श्रृंखला लचीलेपन, स्वच्छ अर्थव्यवस्था, निष्पक्ष अर्थव्यवस्था और समग्र ढांचे के स्थायित्व पर ध्यान केंद्रित किया गया।

इक्कीसवीं सदी के आधे से हिस्से का वैश्विक रूप से जल-तनावग्रस्त क्षेत्रों में होना

संदर्भ: वर्ष 2000 में आधे से अधिक (52%) सिंचाई विस्तार क्षेत्र पहले से ही जल तनाव का सामना कर रहे क्षेत्रों में हुआ, जिसमें भारत ने इस अस्थिर वैश्विक विस्तार में 36% का योगदान दिया।

➤ परिचय:

- संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, फ्रान्स और चीन के शोधकर्ताओं ने सिंचित कृषि के अस्थिर विस्तार की जांच की, जिसमें प्रकृति और मानव आवश्यकताओं के लिए अपर्याप्त जल आपूर्ति सम्बन्धी चिंताओं को उजागर किया गया।
- वैश्विक उपभोग योग्य जल का 90% से अधिक उपयोग सिंचित कृषि के लिए होता है, जो वैश्विक खाद्य उत्पादन में लगभग 40% का योगदान देता है, इसके बावजूद कि सिंचित क्षेत्र केवल 24% फसल भूमि को कवर करते हैं।

➤ वैश्विक सिंचाई विस्तार:

- 8 मार्च, 2024 को नेचर वॉटर जर्नल में प्रकाशित शोध के अनुसार 2000 से 2015 तक सिंचाई के लिए सुसज्जित वैश्विक क्षेत्र (आईआई) में 11% की वृद्धि हुई है, जो 330 मिलियन हेक्टेयर तक पहुंच गई है।
- उत्तर-पश्चिम भारत और उत्तर-पूर्व चीन जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय विस्तार हुआ, जबकि रूस जैसे कुछ क्षेत्रों में गिरावट का अनुभव हुआ।

➤ प्रमुख विस्तार वाले देश:

- चीन और भारत में महत्वपूर्ण शुद्ध विस्तार देखा गया, मुख्य रूप से खाद्य आत्मनिर्भरता बनाए रखने के लिए, चीन में 12.8 मिलियन हेक्टेयर और भारत में 8.5 मिलियन हेक्टेयर की वृद्धि हुई।
- विस्तार के परिणामस्वरूप क्रमशः 65 मिलियन हेक्टेयर और 32 मिलियन हेक्टेयर, कुल क्षेत्रफल में वृद्धि और कमी हुई।

➤ अस्थिर विस्तार की सीमा:

- यह विस्तार उन क्षेत्रों में हुआ जो पहले से ही जल संकट का सामना कर रहे थे, जिससे धारा प्रवाह और जलभृतों में और कमी आई।
- जल तनाव, जिसे हरे पानी के तनाव (जीडब्ल्यूएस) या नीले पानी के तनाव (बीडब्ल्यूएस) के रूप में वर्गीकृत किया गया है, भारत और पाकिस्तान जैसे देशों को प्रभावित करता है, जहां सबसे अधिक विस्तार बीडब्ल्यूएस का अनुभव करने वाले क्षेत्रों में हुआ।

➤ कुछ देशों में सतत विस्तार:

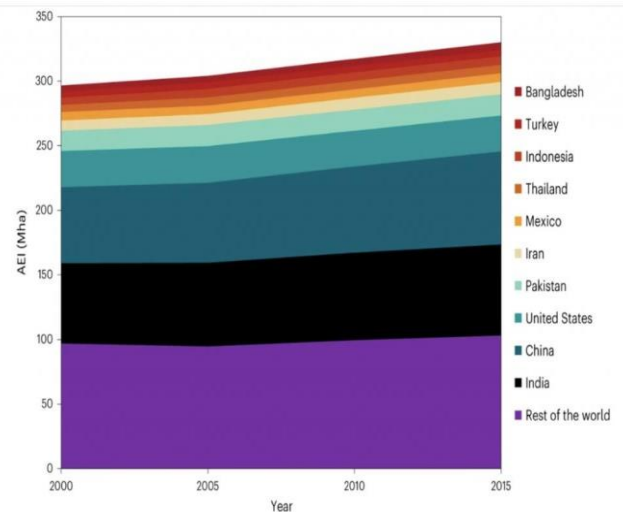
- ब्राजील, इंडोनेशिया, पेरू, इटली और फ्रांस जैसे देशों ने जल संसाधनों पर प्रतिकूल प्रभाव को कम करते हुए ज्यादातर स्थायी विस्तार हासिल किया।

➤ अनुसंधान क्रियाविधि:

- अध्ययन में अंतरराष्ट्रीय डेटाबेस, कृषि जनगणना और सरकारी रिपोर्टों से 17,298 प्रशासनिक इकाइयों को कवर करने वाले उपराष्ट्रीय सिंचाई आंकड़ों का उपयोग किया गया।
- सिंचाई विस्तार प्रवृत्तियों का विश्लेषण करने के लिए वर्ष 2000, 2005, 2010 और 2015 के लिए ग्रिडयुक्त वैश्विक आईआई डेटा विकसित किया गया था।

➤ खाद्य सुरक्षा के निहितार्थ:

- अस्थिर सिंचाई विस्तार खाद्य आत्मनिर्भरता और वैश्विक खाद्य सुरक्षा के लिए जोखिम पैदा करता है, संभावित रूप से फसल उत्पादन को सीमित करता है और खाद्य आयात पर निर्भरता बढ़ाता है।
- निरंतर अस्थिर प्रथाओं से मीठे पानी के संसाधनों की दुर्गमता और आर्थिक बाधाएं पैदा हो सकती हैं, जिससे खाद्य आयात करने वाले और निर्यात करने वाले दोनों देश प्रभावित होंगे।



The global AEI shows a net increase for the period 2000–2015. Countries are arranged in order of increasing AEI (top to bottom) in the year 2000.

Face to Face Centres

DELHI MUKHERJEE NAGAR: 9205274741, 42 | LAXMI NAGAR : 9205212500, 9205962002 | RAJENDRA NAGAR: 9205274743 | UTTAR PRADESH PRAYAGRAJ: 0532-2260189, 8853467068 | LUCKNOW (ALIGANJ): 0522-4025825, 9506256789 | LUCKNOW (GOMTI NAGAR): 7234000501, 7234000502 | GREATER NOIDA: 9205336037, 38 | KANPUR: 7887003962, 7897003962 | GORAKHPUR : 7080847474, 9161947474 | ODISHA BHUBANESWAR: 9818244644/7656949029



dhyeyaias.com



15 March, 2024

NEWS IN BETWEEN THE LINES

विश्व स्मारक कोष



विल्लुपुरम जिले के काडुवेलि इलाके में प्राचीन तालाबों का एक बड़ा जाल है। इन तालाबों को "एरी" कहा जाता है। इस पूरे एरी नेटवर्क को हाल ही में 2025 के लिए वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड वॉच प्रोग्राम में शामिल करने के लिए नामित किया जा सकता है। यह कार्यक्रम दुनिया भर के महत्वपूर्ण स्थानों को सुरक्षित रखने का काम करता है।

विश्व स्मारक कोष के बारे में:

- विश्व स्मारक कोष (डब्ल्यूएमएफ) एक गैर-लाभकारी संगठन है जो वकालत, अनुदान, शिक्षा, प्रशिक्षण और फील्डवर्क के माध्यम से दुनिया के महत्वपूर्ण स्थानों की सुरक्षा के लिए काम करता है।
- इसकी स्थापना 1965 में हुई थी और इसमें विशेषज्ञों की एक वैश्विक टीम है, जिन्होंने 112 देशों में 700 से अधिक सांस्कृतिक विरासत स्थलों को संरक्षित किया है।
- इसका मिशन लोगों के जीवन को समृद्ध बनाना और समुदायों और संस्कृतियों में आपसी समझ का निर्माण करना है।
- इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में है।

ट्रेफिक



हाल ही में, ट्रेफिक और डब्ल्यूडब्ल्यूएफ-इंडिया के एक संयुक्त विश्लेषण ने भारत में अवैध शार्क व्यापार की व्यापकता को प्रकट किया।

ट्रेफिक के बारे में:

- ट्रेफिक (वन्यजीव व्यापार निगरानी नेटवर्क) की स्थापना 1976 में द वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर (डब्ल्यूडब्ल्यूएफ) और द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर (IUCN) द्वारा की गई थी।
- यह एक वैश्विक गैर-सरकारी संगठन है जो जंगली जानवरों और पौधों के व्यापार की निगरानी करता है।
- यह जैव विविधता और टिकाऊ वैध वन्यजीव व्यापार को बनाए रखने के लिए काम करता है साथ ही अवैध वन्यजीव व्यापार का विरोध करता है।
- इसके 20 देशों और क्षेत्रों में पांच महाद्वीपों पर कर्मचारियों का एक अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क है और दर्जनों अन्य देशों में निरंतर शोध कार्य चल रहा है।
- ट्रेफिक 1991 से भारत में है और तब से अवैध वन्यजीव व्यापार को रोकने के लिए अध्ययन, निगरानी और प्रभावी कार्रवाई करने में राष्ट्रीय और राज्य सरकारों और विभिन्न एजेंसियों के साथ मिलकर काम कर रहा है।
- ट्रेफिक की प्रमुख परियोजनाओं में वन्यजीव व्यापार निगरानी नेटवर्क (डब्ल्यूटीएमएन), ग्लोबल शार्क एंड रे इनिशिएटिव (जीएसआरआई), पैगोलिन संरक्षण, टिबर व्यापार और वन अपराध, वन्यजीव साइबर अपराध और हाथीदांत और गैंडे के सींग की मांग में कमी शामिल हैं।

वोकल फॉर लोकल



हाल ही में नीति आयोग ने जमीनी स्तर पर उद्यमिता और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम के तहत 'वोकल फॉर लोकल' कार्यक्रम की शुरुआत की है।

वोकल फॉर लोकल के बारे में:

- 'वोकल फॉर लोकल' एक पहल है जिसका उद्देश्य भारत में जमीनी स्तर की उद्यमिता और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है।
- यह पहल मुख्य रूप से स्थानीय स्वदेशी उत्पादों के उत्पादन और खपत को प्रोत्साहित करने पर केंद्रित है जिससे आकांक्षी ब्लॉकों में सूक्ष्म उद्यमों को सशक्त बनाया जा सके।
- लॉन्च इवेंट के दौरान, 'आकांक्षा' के लोगो का अनावरण किया गया, जो स्थानीय उत्पादों को प्रभावी ढंग से ब्रांड करने और बढ़ावा देने की पहल का एक हिस्सा है।
- एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में, 500 आकांक्षी ब्लॉकों के स्वदेशी उत्पादों को 'आकांक्षा' पहल के तहत सावधानीपूर्वक मानचित्रित और समेकित किया गया है।
- आकांक्षी ब्लॉकों से उत्पादों की खरीद और प्रचार की सुविधा के लिए 'आकांक्षा' ब्रांड नाम के तहत GeM पोर्टल पर एक समर्पित विंडो स्थापित की गई है।
- ई-कॉमर्स ऑनबोर्डिंग, वित्तीय/डिजिटल साक्षरता, दस्तावेजीकरण/प्रमाणन और कौशल वृद्धि सहित विभिन्न पहलुओं के लिए तकनीकी और परिचालन सहायता प्रदान की जाती है।
- 'वोकल फॉर लोकल' पहल महत्वपूर्ण महत्व रखती है क्योंकि यह स्थानीय व्यवसायों के लिए अनुकूल माहौल बनाने का प्रयास करती है, जिससे आर्थिक सशक्तिकरण होता है और विभिन्न क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलता है।

हृदय रोग (सीवीडी)



हाल ही में एक वैश्विक अध्ययन ने इस पारंपरिक धारणा को चुनौती दी है कि अत्यधिक गरीबी में रहने वाले लोगों में आहार और व्यावसायिक पैटर्न के कारण हृदय रोग (सीवीडी) के जोखिम कारक कम होते हैं।

हृदय रोग (Cardiovascular Disease) के बारे में:

- हृदय रोग हृदय और रक्त वाहिकाओं के विकारों के एक समूह को संदर्भित करता है, जिसमें कोरोनरी धमनी रोग, स्ट्रोक, हृदय विफलता और उच्च रक्तचाप शामिल हैं।
- यह विश्व स्तर पर रुग्णता और मृत्यु दर का एक प्रमुख कारण है, जो सभी उम्र और सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि के व्यक्तियों को प्रभावित करता है।
- सीवीडी के प्रमुख जोखिम कारकों में उच्च रक्तचाप, मधुमेह, धूम्रपान, मोटापा, उच्च कोलेस्ट्रॉल स्तर (डिस्लिपिडेमिया), अस्वास्थ्यकर आहार, शारीरिक निष्क्रियता और अत्यधिक शराब का सेवन शामिल हैं।
- यह वैश्विक मौतों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और निम्न और मध्यम आय वाले देशों में इसका बोझ अधिक है।
- नवोन्मेषी स्वास्थ्य सेवा वितरण मॉडल, जैसे घर पर स्वास्थ्य सेवा सेवाएं और समुदाय-आधारित हस्तक्षेप, का उद्देश्य विशेष रूप से हाशिए पर रहने वाली आबादी के लिए देखभाल तक पहुंच में सुधार करना है।

Face to Face Centres





15 March, 2024

सुर्खियों में स्थल

साइप्रस

हाल ही में, गाजा को सहायता पहुंचाने के लिए एक पायलट परियोजना के तहत 200 टन सहायता ले जाने वाला एक जहाज साइप्रस से रवाना हुआ। यह जहाज पांच महीने के युद्ध के बाद अकाल का सामना कर रही आबादी को आपूर्ति पहुंचाने के लिए एक समुद्री गलियारा स्थापित करने का प्रयास है।

साइप्रस (राजधानी: निकोसिया)

अवस्थिति : साइप्रस, जिसे आधिकारिक तौर पर साइप्रस गणराज्य के रूप में जाना जाता है, सिसिली और सार्डिनिया के बाद पूर्वी भूमध्य सागर में तीसरा सबसे बड़ा द्वीप देश है।

राजनीतिक सीमाएँ: साइप्रस सीरिया (पूर्व), लेबनान और इजराइल (दक्षिणपूर्व), तुर्की (उत्तर) और मिस्र (दक्षिण) सहित कई देशों के साथ समुद्री सीमाएँ साझा करता है।

भौतिक विशेषताएँ:

- साइप्रस का सबसे ऊँचा स्थान माउंट ओलंपस (जिसे चियोनिस्ट्रा भी कहा जाता है) है, जो द्वीप के मध्य भाग में टूडोस पर्वत में स्थित है।
- साइप्रस में कुछ प्रमुख नदियाँ हैं, जिनमें पेडियोस नदी सबसे लंबी है, जो टूडोस पर्वत से मेसोरिया मैदान और भूमध्य सागर में बहती है।
- इस द्वीप की जलवायु भूमध्यसागरीय है।
- साइप्रस में खनन का एक लंबा इतिहास है जिसमें तांबा, एस्बेस्टस, जिप्सम और मिट्टी के महत्वपूर्ण भंडार हैं।



POINTS TO PONDER

- हाल ही में महाराष्ट्र के किस जिले का नाम बदलकर 18वीं सदी की मराठा रानी अहिल्याबाई होल्कर के नाम पर रखा गया है? – **अहमदनगर (अहमदनगर को अहिल्यानगर कहा जाएगा)**
- हाल ही में त्रि-सेवा फायरिंग और युद्धाभ्यास - भारत शक्ति किस स्थान पर आयोजित किया गया था? – **पोखरण, राजस्थान**
- 12 मार्च को प्रधानमंत्री द्वारा पुनर्विकसित कोचरब आश्रम के उद्घाटन से कौन सी ऐतिहासिक घटना जुड़ी है? – **नमक सत्याग्रह मार्च या दांडी मार्च (12 मार्च 1930)**
- दी गई जानकारी के अनुसार हाल ही में किन तीन देशों ने ओमान की खाड़ी में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास शुरू किया है? – **चीन, ईरान और रूस**
- प्रदान की गई जानकारी के अनुसार हाल ही में किस नौसैनिक संपत्ति ने रूस के बाल्टिस्क नौसैनिक अड्डे से अपना समुद्री परीक्षण शुरू किया? – **आईएनएस तुशिल**

Face to Face Centres

